भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 539

बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

अनूसूचित जाति समुदायों के लिए अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग

***539. डॉ. डी. रवि कुमार:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति समुदायों के कल्याण के लिए अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जमीनी स्तर पर इस संबंध में कोई जागरूकता कार्यक्रम मौजूद हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन अनुप्रयोगों के लाभ अनुसूचित जाति के किसानों, छात्रों और आपदा प्रवण क्षेत्रों तक पहुँच रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का समावेशी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) से (घ)

इस संबंध में सभा के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

*****

"अनुसूचित जाति समुदायों के लिए अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग" के संबंध में बुधवार, 01 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने हेतु डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 539 के जवाब में लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत विवरण।

(क) जी हाँ। इसरो ने अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला का विकास और संचालन किया है, जो अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण सहित समाज के सभी समुदायों को लाभान्वित कर रही है। कुछ प्रमुख अंतरिक्ष अनुप्रयोग के क्षेत्रों में उपग्रह आधारित संभावित मत्स्य क्षेत्र (पीएफजेड), फसल क्षेत्र और उत्पादन पूर्वानुमान; किसानों के लिए कृषि-मौसम संबंधी सलाह; फसल बीमा सहायता, प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों के लिए भू-स्थानिक सहायता, दूरवर्ती-शिक्षा, दूरस्थ-चिकित्सा, पोत संचार एवं सहायता प्रणाली, आपदा प्रबंधन सहायता आदि शामिल हैं।

(ख) जी हां। इसरो ने सामाजिक, अभिशासन और आपदा प्रबंधन संबंधी सहायता के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सशक्त जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम स्थापित किए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले निर्णयकर्ताओं को लाभ मिल रहा है। ये जागरूकता पहल समावेशी पहल के रूप में डिज़ाइन किए गए हैं और देश भर के सभी लक्षित नागरिकों के लिए सुलभ हैं।

(ग) भू-प्रेक्षण, उपग्रह संचार, नौवहन अनुप्रयोगों के लाभ बेहतर कनेक्टिविटी और नौवहन संबंधी सूचना के संदर्भ में उपग्रह के कवरेज क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति के किसानों, छात्रों और आपदा-प्रवण क्षेत्रों तक पहुंचते हैं।

(घ) विभाग ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के समावेशी उपयोग के लिए डिजिटल इंडिया, भारतनेट कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पोत संचार और सहायता प्रणाली (वीसीएसएस) परियोजना तथा दूरवर्ती शिक्षा के लिए पीएम ई-विद्या योजना आदि जैसे विभिन्न प्रमुख पहलों के कार्यान्वयन हेतु अनेक कदम उठाए हैं।

***